



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-31/2015

बउनवान

श्री मुरारी आयु 26 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी सीसवाली जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, सीसवाली जिला बारां
(रिस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक **(अपीलांट)**
2- पेरोकार सरकार **(रिस्पोंडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 28.06.2019

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के प्रकरण संख्या 54/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2014 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सीसवाली की किस्म बारानी 1 भूमि खसरा नम्बर 1501 की रकबा 0.24 हेक्टर भूमि पर ईटभट्टा लगाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह (30 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 1950/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.03.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रिस्पोंडेन्ट को जयें सम्मन तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, पत्रावली में बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, उक्त विवादित आराजी खातेदारी की भूमि है, जिस पर अपीलांट द्वारा ईट भट्टा संचालित किया जा रहा है। अपीलांट के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत की गई है, श्रीमान चाहे तो पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय से मौका रिपोर्ट मय नक्शा मंगवायी जावे ताकि प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है अपीलांट जाति से कुम्हार है एवं ईट निर्माण उसका पुश्तेनी व्यवसाय है, अपीलांट वर्णित आराजियात कर पिछले कई वर्षों से ईटो का भट्टा लगाकर अपने परिवार का पेट पालन करता चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जाकर, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली को आदेश दिये गये कि मौके पर जाकर जांच करवाकर मय नक्शा स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाये जावे। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.2015 को मौके पर, मय नक्शा रिपोर्ट तैयार की जाकर, पत्रांक 876 दिनांक 19.8.2015 से इस न्यायालय को प्रेषित की गई।

इसके विपरीत सरकारी परोकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था। तामील प्रोपर हुई है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना नहीं हुई है। अपीलांत बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1501 की रकबा 0.24 हेक्टर बराना है जो सरकारी है जिस पर अप्रार्थी ने नाजायज अतिक्रमण कर लिया है ग्रामवासियान में उक्त आराजी पर अतिक्रमण से भारी रोष व्याप्त है। अप्रार्थी एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो सरकारी भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, पूर्व में भी अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2070 में अतिक्रमण किया गया था, जिसको प्रकरण संख्या 23/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.2.2014 से बेदखल किया जा चुका था। अपीलांत द्वारा सम्वत् 2071 में पुनः किया गया ईट भट्टा लगाकर अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। उक्त ईट भट्टे पर प्रतिदिन बनाये जाने वाली ईटों की संख्या 300-1000 जप्ति के समय पक्की ईटों की संख्या लगभग 60000 कच्ची ईटों की संख्या 20000 अनुमानित, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 150000 है। प्रकरण में ऐसे अतिक्रमी की सजा माफ किया जाना न्यायोचित नहीं है इससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। उक्त ईट भट्टा आबादी के समीप स्थित है जो अवैध है ओर उसके लिये प्रदूषण विभाग की अनुमति लिया जाना भी आवश्यक है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अपीलांत के अभिभाषक एवं परोकार सरकार की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया, साथ ही प्रकरण में आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस ली गई, जिसका अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 54/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 वाके ग्राम सीसवाली की किस्म बरानी 1 भूमि खसरा नम्बर 1501 की रकबा 0.24 हेक्टर भूमि पर ईट भट्टा लगाकर किये गये अतिक्रमण के परिपेक्ष्य में अपीलांत के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये पारित किया गया है। जिस पर अपीलांत द्वारा आपत्ति की गई की उक्त आराजी खातेदारी की है, जहाँ ईट भट्टा संचालित है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय से मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तलब की गई। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.2015 को तैयार की गई, जिसके मुताबिक ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर 1489 रकबा 1.53 हैक्ट. किस्म बरानी 1 खातेदार मुरारी पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी सीसवाली के खातेदारी की है। वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 1489 की रकबा 0.30 हेक्टर पर खातेदारी की भूमि पर पक्की ईट बनाये जाने हेतु ईट भट्टा मुरारी पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी सीसवाली का संचालित है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा अपीलांत के विरुद्ध ग्राम सीसवाली के खसरा नम्बर 1501 की रकबा 0.24 हेक्टर किस्म बरानी 1 पर अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर, अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई है, जो नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा आई.एल.आर. के माध्यम से तैयार कर प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दिनांक 25.6.2015 से मेल नहीं

खाती है। अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली के निर्णय दिनांक 15.12.2014 में खसरा नम्बर 1501 की रकबा 0.24 हेक्टर भूमि पर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। जबकि दिनांक 25.6.2015 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांत का कब्जा इस खसरा नम्बर न होकर अन्य खातेदारी की भूमि वाके ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1489 रकबा 1.53 हैक्ट. किस्म बारानी 1 खातेदार मुरारी पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी सीसवाली के खातेदारी पर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2014 में तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 54/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांत को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि नायब तहसीलदार सीसवाली 7 दिवस में जाँच करे, कि अपीलांत यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम सीसवाली की खसरा नम्बर 1501 की रकबा 0.24 हेक्टर भूमि किस्म बारानी 1 से कब्जा छोड़ दिया है, तो नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 54/2014 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2014 यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां